राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 11183/2022

राजेंद्र उर्फ राजूराम पुत्र नंदाराम, उम्र लगभग 46 वर्ष, कुकनवाली, पी.एस. चितावा, जिला नागौर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, द्वितीय तल, पंचम ब्लॉक, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर - 302017 के माध्यम से।
2. राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, अपने सचिव शिक्षा संकुल परिसर, जेएलएन मार्ग, जेएलएन मार्ग, जयपुर, राजस्थान 302001 के माध्यम से

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री नमन मोहनोत।
श्री हिमांशू पारीक।
सुश्री मनीषा फोफलिया।

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री पी.आर. सिंह.

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>04/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत, जो शिक्षाकर्मी (शिक्षक) के रूप में काम कर रहा था, जो एक स्वैच्छिक पद है, जिसके लिए उसे केवल कुछ मानदेय देय है, 14.01.1998 के एक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

2. याचिकाकर्ता का दावा है कि उक्त समाप्ति आदेश अवैध है क्योंकि इसका आधार केवल प्रासंगिक समय पर एक एफआईआर का पंजीकरण था और याचिकाकर्ता द्वारा अपराध किए जाने की दोषसिद्धि के बिना, उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता था।

3. मामले के सुसंगत तथ्य, जैसा कि तर्क दिया गया है, इस प्रकार हैं:

3.1. याचिकाकर्ता ने बताया कि व्यक्तिगत विवाद के कारण, याचिकाकर्ता के खिलाफ उसकी छात्रा की मां ने पुलिस स्टेशन चितावा, जिला नागौर में दिनांक 08.05.2022 को एफआईआर संख्या 0081/2022 (अनुलग्नक 2) दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 363, 354, 504, पोक्सो अधिनियम की धारा 7, 8 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(एस) के तहत अपराध दर्ज किए गए थे। याचिकाकर्ता को दिनांक 09.05.2022 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के कारण, उसे दिनांक 11.05.2022 के आदेश (अनुलग्नक 3) के तहत दिनांक 08.05.2022 से उसकी सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

3.2. उसी दिन यानी 11.05.2022 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद, उन्होंने 17.05.2022 को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया (अनुलग्नक 6)। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2 ने सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, दिनांक 08.06.2022 के आदेश (अनुलग्नक 7) के तहत याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दीं। इसलिए, यह रिट याचिका।

4. जवाब में बचाव पक्ष यह है कि याचिकाकर्ता ने यह तथ्य गलत तरीके से प्रस्तुत किया है कि उसे सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वास्तव में, वह समाज सेवा के आधार पर शिक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत था और उसे मानदेय दिया जा रहा था। वह राजस्थान सेवा नियम, 1958 द्वारा शासित नहीं है।

4.1 नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर याचिकाकर्ता को 08.05.2022 से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद, सचिव, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता की सेवाएं 08.05.2022 से समाप्त कर दी गईं। इसलिए, याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने में प्रतिवादियों ने न्यायोचित कार्य किया है और इस प्रकार, याचिका खारिज होने योग्य है।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं।

6. यहाँ संक्षिप्त विवाद यह है कि क्या प्रतिवादी अपने विवेक का प्रयोग केवल इसलिए कर सकते थे क्योंकि याचिकाकर्ता एक एफआईआर में शामिल होने के आधार पर स्वयंसेवक के रूप में सेवाएं दे रहा था, जिसके लिए मुकदमे में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। उत्तर अनिवार्य रूप से नकारात्मक है।

6.1. यह स्थापित स्थिति है कि केवल एफआईआर दर्ज होना ही उसे रोजगार न देने का आधार हो सकता है, वह भी तब, जब वह किसी कर्मचारी के कर्तव्यों पर असर डालता हो या किसी भी तरह की नैतिक अधमता को दर्शाता हो। इस मामले

में याचिकाकर्ता पहले से ही अपनी सेवाएं दे रहा था, इसलिए प्रतिवादियों को अधिक सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि सेवा समाप्ति आदेश से याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि का पता लगाए बिना ही कलंक लग सकता था। जैसा कि पता चला, मुकदमे के समापन पर याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया। इस हद तक, वह इस बात से सही साबित हुआ कि उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था।

7. इस आधार पर, आक्षेपित समाप्ति आदेश टिकाऊ नहीं है और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। हालाँकि, अजीबोगरीब कार्य व्यवस्था को देखते हुए, जो कि केवल स्वैच्छिक प्रकृति की है और केवल मानदेय देय है, प्रतिवादी याचिकाकर्ता को स्वयंसेवक के रूप में फिर से शामिल करने के लिए बाध्य नहीं हैं, यदि वर्तमान में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

8. निपटारा किया गया।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि ऐसी स्वैच्छिक सेवाओं की आवश्यकता है तो याचिकाकर्ता के आवेदन पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा और पिछला समाप्ति आदेश उसके आड़े नहीं आएगा और इसे किसी प्रकार का कलंक नहीं माना जाएगा।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।